[2013] 9 एस.सी.आर. 692

रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बरेली

बनाम

भारतीय चिकित्सा परिषद और अन्य

(रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 585, 2012

सितम्बर 06, 2013

[के.एस. राधाकृष्णन और ए.के. सीकरी, जे.जे.]

मेडिकल कॉलेज विनियमन (संशोधन 2010 भाग II)

खंड 8(3)(1)(डी) - अनुमति/मान्यता का निरसन एमबीबीएस डिग्री प्रदान करने हेतु - नवीनीकरण हेतु अनुमोदन मेडिकल कॉलेज को 100 से अधिक संख्या की अनुमति शैक्षणिक वर्ष 2013-2014 के लिए 150 सीटें - एमसीआई द्वारा निरस्त साजिश के संबंध में सी.बी.आई. से सूचना प्राप्त होने पर एक पर मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन के बीच केंद्रीय मंत्रालय के हाथ और सार्वजनिक पदाधिकारी और दूसरी ओर सरकारी अस्पताल, जिसे जारी करने के लिए जेड शैक्षणिक हेतु छात्रों के अतिरिक्त प्रवेश हेतु आदेश पारित वर्ष 2008-2009 - आयोजित: सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में बताया निरीक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में गंभीर खामियाँ केंद्रीय मंत्रालय द्वारा गठित टीम-सीबीआई जांच कर चुकी है खुलासा हुआ कि केंद्रीय टीम द्वारा

भी धोखाधड़ी की गई थी कॉलेज को एमबीबीएस के तीसरे बैच के लिए मंजूरी मिलनी है शैक्षणिक वर्ष 2008-09 के लिए छात्र - यह पर्याप्त था एमसीआई को कार्रवाई करने और अनुमति के जेट्टर को रद्द करने के लिए कहा गया है शैक्षणिक वर्ष 2013-14 के लिए प्रदान किया गया - एमसीआई का निर्णय है विनियम 8(3)(1)(डी) के अनुसार - न्यूनतम 100 के लिए मेडिकल कॉलेज के लिए मानक आवश्यकताएँ वार्षिक प्रवेश विनियम, 1999

भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956:

एस.एस. 10ए और 19ए - एस. 10ए, यह अनिवार्य करता है कि जब कोई नया हो मेडिकल कॉलेज की स्थापना होनी है या सीटों की संख्या बढ़ाया जाना है, केंद्र सरकार की अनुमति है पूर्व अपेक्षित - एस. 19ए एमसीआई को न्यूनतम निर्धारित करने के लिए बाध्य करता है चिकित्सा शिक्षा के लिए आवश्यक मानक और एमसीआई द्वारा केंद्र सरकार को दी गई सिफारिशें काफी वजन - मौजूदा मामले में एमसीआई लगातार चालू है तमाम मौकों पर केंद्र सरकार को सिफारिश नहीं की गई के तीसरे बैच के प्रवेश हेतु अनुमति के नवीनीकरण हेतु शैक्षणिक वर्ष 2008 09, लेकिन इसके बावजूद, एक केंद्रीय टीम नियुक्त की गई, अनुकूल रिपोर्ट मिली और वर्ष के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गई 2008-09, जो कि सी.बी.आई. जांच का विषय था।

शिक्षा/शैक्षिक संस्थान:

मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश - कोर्ट ने संज्ञान लिया चिंता, तकनीकी और चिकित्सा की अभूतपूर्व वृद्धि की देश में जिन संस्थाओं का व्यापक परिणाम हुआ है विभिन्न अनैतिक प्रथाओं के प्रचलन और जोर दिया गया कि संसदीय विधान की अत्यंत आवश्यकता है इन अनुचित प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए - विधान - न्यायिक सूचना - भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 21.

याचिकाकर्ता-मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल थे वर्ष 2005 में स्थापित। इसने पहला एम.बी.बी.एस. शुरू किया। वर्ष 2006-07 के दौरान वार्षिक प्रवेश के साथ पाठ्यक्रम द्वारा जिन 100 सीटों की अनुमति दी गई थी केंद्र सरकार भारतीय चिकित्सा परिषद के यूएलएस 10ए अधिनियम, 1956. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) ने दी कॉलेज को एम.बी.बी.एस. पुरस्कार देने की मान्यता द्वारा डिग्री संबंधित विश्वविद्यालय. कॉलेज ने बाद में एक प्रस्तुत किया नवीनीकरण की अवधि बढ़ाने के लिए एमसीआई को आवेदन की 100 सीटों के तीसरे बैच में प्रवेश की अनुमति एम.बी.बी.एस. शैक्षणिक वर्ष 2008-09 के लिए. इसके बाद एमसीआई कॉलेज का निरीक्षण करवाना, इत्यादि निरीक्षण टीमों की रिपोर्ट की प्राप्ति और अनुपालन कॉलेज द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, सेंट्रल को सूचित किया गया शासन के पत्र दिनांक 16.04.2008, 14.6.2008 एवं 4.9.2008 के प्रवेश

हेतु अनुमति का नवीनीकरण न करना शैक्षणिक सत्र 2008-09 के लिए छात्रों का तीसरा बैच। की रिपोर्ट प्राप्त होने पर केन्द्र सरकार गठित निरीक्षण टीम ने भी कॉलेज से पूछा 27.7.2008 को एमबीबीएस के किसी भी नए बैच को प्रवेश नहीं देने का आदेश शैक्षणिक वर्ष 2008-09 के लिए छात्र। हालाँकि, पर 12.9.2008 को महाविद्यालय ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया एमबीबीएस के 50 विद्यार्थियों को प्रवेश की अनुमति प्रदान करना शैक्षणिक सत्र 2008-09 इसके बाद केंद्रीय मंत्रालय दो डॉक्टरों की एक और टीम गठित की, जिन्होंने संचालन किया दिनांक 25.9.2009 को महाविद्यालय का निरीक्षण एवं आधार इसकी रिपोर्ट का केंद्र सरकार ने पत्र जारी किया दिनांक 26.9.2008 के अनुसार नवीनीकरण हेतु स्वीकृति 100 छात्रों के तीसरे बैच के प्रवेश की अनुमति शैक्षणिक वर्ष 2008-09

एमसीआई ने दिनांक 20.06.2013 को अपने पत्र द्वारा इसकी जानकारी दी के नवीनीकरण हेतु अनुमोदन आदेश दिनांक 4.6.2013 एमबीबीएस के दूसरे बैच में प्रवेश की अनुमति विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि के विरूद्ध अर्थात् 100 से 150 तक शैक्षणिक वर्ष 2013-14 के लिए कॉलेज में सीटें। में इस बीच, एमसीआई को दिनांकित एक गोपनीय पत्र प्राप्त हुआ 11.07 .2013 केंद्रीय जांच ब्यूरो से ने जानकारी देते हुए बताया कि के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है महाविद्यालय के अध्यक्ष एवं केन्द्रीय मंत्रालय के अधिकारीगण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग,

आईपीसी की धारा 1208 और धारा के तहत 13(2) एस के साथ पढ़ें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी), 1988. साथ में एक आरोप पत्र भी संलग्न किया गया था पत्र। एमसीआई ने दिनांक 13.7.2013 के आदेश द्वारा इसे रद्द कर दिया निर्णय दिनांक 04.06.2013 और, उसे सूचित किया गया कॉलेज के लिए कॉलेज ने उक्त की वैधता को चुनौती दी।

तत्काल रिट याचिका पर फैसला कोर्ट ने रिट याचिका खारिज करते हुए आयोजित:

1.1. विशेषकर मेडिकल काउंसिल अधिनियम, 1956 एस। उसका 1 ओए यह अनिवार्य करता है कि जब कोई नया मेडिकल कॉलेज बनेगा एच की स्थापना की जानी है या सीटों की संख्या होनी है बढ़ी, केंद्र सरकार की अनुमति है ए पूर्व अपेक्षित. धारा 19ए एमसीआई को निर्धारित करने के लिए बाध्य करती है चिकित्सा शिक्षा के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक और एमसीआई ने केंद्र से की सिफारिश सरकार के पास काफी वजन है, यह एक है विशेषज्ञ निकाय. एमसीआई ने निर्धारित किया है नियम- "चिकित्सा के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकताएँ वार्षिक 100 प्रवेशों के लिए कॉलेज विनियम, 1999"। न्यूनतम आवश्यकताओं को सत्यापित करने के लिए एमसीआई को मिलता है निरीक्षण निरीक्षकों द्वारा किया जाता है, जो विशेषज्ञ हैं और कर्मचारियों की उपलब्धता पर अपनी रिपोर्ट

प्रस्तुत करें - शिक्षण और निवासी - और अन्य बुनियादी ढाँचा नियमों के अनुसार सुविधाएं, नैदानिक उपलब्धता आदि। [पैरा 28] [713-जी-एच; 714-ए-सी]

1.2. मौजूदा मामले में एमसीआई लगातार सभी पर अवसरों, केंद्र सरकार को अनुशंसित नहीं डी तीसरे बैच के प्रवेश हेतु अनुमति के नवीनीकरण हेतु शैक्षणिक वर्ष 2008-09, लेकिन इसके बावजूद, ए केन्द्रीय टीम नियुक्त की गई, अनुकूल रिपोर्ट मिली और केंद्र सरकार द्वारा अनुमति दे दी गई वर्ष 2008-09 के लिए. सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में स्पष्ट रूप से बताया गया कि यह के आधार पर किया गया था फर्जी, नकली और जाली रिकॉर्ड। सीबीआई ने देखा कि कॉलेज के अधिकारियों ने मनगढ़ंत और जाली उत्पादन किया था निरीक्षण टीम और टीम के समक्ष दस्तावेज फेल हो गए उन दस्तावेज़ों की सत्यता या अन्यथा को सत्यापित करने के लिए। एफ सीबीआई जांच में धोखाधड़ी की बात सामने आई है प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय टीम के साथ-साथ महाविद्यालय द्वारा भी अभ्यास किया गया एमबीबीएस छात्रों के तीसरे बैच के लिए मंजूरी शैक्षणिक वर्ष 2008-09. सीबीएल की जांच प्रथम दृष्टया अध्यक्ष जी के बीच आपराधिक साजिश स्थापित करता है कॉलेज के और तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और तत्कालीन उप सचिव सहित परिवार कल्याण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और दो डॉक्टर सरकारी अस्पताल

जिसके कारण जारी किया गया के लिए 50 विद्यार्थियों के अतिरिक्त प्रवेश का आदेश पारित किया गया शैक्षणिक वर्ष 2008-09 26.09.2008 को। इसमें सी.बी.आई आरोप-पत्र, रिपोर्ट में गंभीर कमज़ोरियों की ओर इशारा करता है केंद्रीय टीम द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसने संचालन किया 25.09.2008 को महाविद्यालय का निरीक्षण। [पैरा 25-27 और 29) [709-जी-एच; 710-बी-सी; 713-ई-जी; 714-डी-ई]

1.3. कब मंजूरी दी गई और पत्र दिनांक 20.06.2013 द्वारा सूचित किया गया था एमसीआई ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसा ही था कुछ शर्तों के अधीन प्रदान किया गया। ऐसा कहा गया था झूठी/गलत घोषणा या मनगढ़ंत दस्तावेजों के मामले में के बोर्ड की अनुमति प्राप्त करने के लिए उपयोग किया गया था राज्यपालों का सेवन बढ़ा हुआ है और यदि कहा जाए तो कदाचार भी संज्ञान में लाया गया या जानकारी में आया चालू शैक्षणिक वर्ष के दौरान किसी भी स्तर पर एमसीआई (2013-14) संस्था/कॉलेज इसके हकदार नहीं होंगे के विरूद्ध अनुमति के नवीनीकरण हेतु विचार किया गया अगले शैक्षणिक वर्ष और उसके लिए प्रवेश में वृद्धि के लिए बढ़ी हुई सेवन के विरुद्ध अनुमति का नवीनीकरण शैक्षणिक वर्ष 2013-14 और अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए निरस्त किया जा सकेगा। पत्र मिला है सी.बी.आई. के साथ-साथ आरोप-पत्र पर भी निर्णय लिया गया एमसीआई द्वारा 13.07.2013 को अनुमति पत्र रद्द कर दिया गया शैक्षणिक

वर्ष 2013-14 के लिए प्रदान किया गया चिकित्सा की स्थापना के खंड 8(3)(1)(डी) के साथ कॉलेज विनियमन (संशोधन 2010 भाग II), जो कहा गया है कि जब एमआईसी को पता चलता है कि कॉलेज ने नियोजित किया है अनुमति के नवीनीकरण के लिए फर्जी/जाली दस्तावेज/ आवेदनों के प्रसंस्करण आदि के लिए उस संस्थान को मान्यता के नवीनीकरण हेतु विचार नहीं किया जा सकेगा एमबीबीएस डिग्री प्रदान करने के लिए अनुमति/मान्यता/ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन पर कार्रवाईदो शैक्षणिक वर्ष अर्थात वह शैक्षणिक वर्ष और अगला शैक्षणिक वर्ष। [पैरा 30-32 और 35] [714-एफ-एच; 715-ए-बी;717-सी-डी]

1.4. एमसीआई को मुकदमे की समाप्ति तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर शुरू की गई। इसकी जांच सीबीआई जैसी प्रमुख एजेंसी ने की है प्रथम दृष्टया पता चला कि कॉलेज ने फर्जी और का प्रयोग किया है वर्ष के लिए सेवन की मंजूरी पाने के लिए जाली सामग्री 2008-09 और यह एमसीआई के लिए कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त है 2013 के विनियम 8(3)(1)(डी) के अनुसार विनियम. [पैरा 36 [717-एफ-जी]

न्यायालय की चिंता

2.1. हालांकि, सीबीआई की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है ऐसी स्थिति, जो आंखें खोलने वाली है भविष्य में उचित उपचारात्मक उपाय करें

ताकि चिकित्सा शिक्षा आईएमसी अधिनियम द्वारा परिकल्पित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती है और विनियम और समुदाय की सेवा करें। ये दर्शाता है हमारी शिक्षा व्यवस्था का गिरता स्तर उच्चतम स्तर; कभी-कभी केन्द्रीय स्तर पर भी सरकार जीवन के अधिकार पर गंभीरता से काम कर रही है कला के तहत देश के नागरिकों को गारंटी। 21 का संविधान। [पैरा 39] [719-बी-सी, डी-ई]

टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन और अन्य बनाम कामताका राज्य और अन्य 2002 (3) पूरक। एससीआर 587 (2002) 8 सेकंड 481 और पी.ए. एलनामदार और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य 2005 (2) पूरक। एससीआर 603 = (2005) 6 एससीसी 537 - करने के लिए भेजा।

2.2. कोर्ट ने चिंता जताते हुए संज्ञान लिया तकनीकी एवं चिकित्सा की अभूतपूर्व वृद्धि देश में जिन संस्थाओं का परिणाम हुआ है विभिन्न अनैतिक प्रथाओं का व्यापक प्रसार। कैपिटेशन शुल्क के माध्यम से बड़ी राशि का संग्रहण, ऐसे कई स्वंयवरों द्वारा अत्यधिक शुल्क, दान आदि वित्तीय संस्थाओं ने मेधावियों को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखा है गरीब छात्र उन संस्थानों से दूर हो गए। यह न्यायालय कई बार इस तथ्य का न्यायिक नोटिस भी ले सकता है मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज आदि हैं ऋण के माध्यम से बड़ी रकम प्राप्त करने के बाद स्थापित किया गया वित्तीय संस्थानों और अन्य उधारों से, H698 के साथ सर्वोच्च

न्यायालय की रिपोर्ट अपना कोई फंड नहीं, और एक बार कॉलेज को मंजूरी मिल जाए और छात्रों को प्रवेश दिया गया है, लिया गया ऋण चुकाया जा रहा है छात्रों से ली जाने वाली कैपिटेशन फीस से और अंततः वह राशि उनकी पूंजी बनती है। कई ए कई बार तो वे बिना किसी पर्याप्त सुविधा के भी काम करते हैं विभिन्न एजेंसियों और केंद्र पर दबाव सरकार और नियामक की अनदेखी कर मंजूरी लें एमसीआई जैसी अथॉरिटी, जो गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है चिकित्सीय शिक्षा। [पैरा 24 और 27] [709-डी-ई; 713-8-डी]

2.3. न्यायालय ने वर्तमान नीति पर भी ध्यान दिया उच्च शिक्षा में केंद्र सरकार है संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करें, लेकिन इसे अपनाना अनुचित है प्रथाएँ कानून का गंभीर उल्लंघन है। कुछ राज्य मांग पर रोक लगाने के लिए कुछ कानून पारित किए हैं/ कैपिटेशन शुल्क का संग्रह जिसमें कोई दांत नहीं है जो संस्थान इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं वे बच सकते हैं कुछ जुर्माना अदा करके, जो बहुत कम है। यह इसलिए है, इस बात पर बल दिया कि इसकी अत्यधिक आवश्यकता है इन अन्यायों पर अंकुश लगाने के लिए संसदीय विधान अभ्यास. [पैरा 41-42) [720-8-ई]

केस कानून संदर्भ:

2002 (3) पूरक। एससीआर 587 पैरा 38 को संदर्भित करता है

2005 (2) पूरक। एससीआर 603 को पैरा 38 में संदर्भित किया गया है

सिविल मूल क्षेत्राधिकार: रिट याचिका (सिविल) संख्या.

2013 का 585 भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

राकेश क्र. खन्ना, एएसजी, मुकुल रोहतगी, गुरु कृष्णा कुमार, मुकुल गुप्ता, अमरेन्द्र शरण, अबधेश चौधरी, अमित जयसवाल, राजीव रंजन द्विवेदी, अमित कुमार, अविजित मणि त्रिपाठी, ऋतुराज कुमार, वी. मोहना, अनिरुद्ध तंवर, दुष्यन्त अरोड़ा, मुद्रिका बंसल, कोमल जयसवाल, बी. सुब्रमण्यम उपस्थित पक्षों के लिए प्रसाद।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

के.एस. राधाकृष्णन, जे. 1. याचिकाकर्ताओं के पास है इस न्यायालय द्वारा प्रदत्त असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग किया गया भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत पत्र को रद्द करने के लिए दिनांक 13.07.2013 को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया जिसके लिए प्रवेश नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की गई शैक्षणिक सत्र 2013 के लिए छात्रों का अतिरिक्त प्रवेश- 2014 को निरस्त कर दिया गया।

2. रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल था रोहिलखंड एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा स्थापित वर्ष 2005. मेडिकल कॉलेज ने पहला एम.बी.बी.एस. शुरू किया। वर्ष 2006-07 के दौरान 100 की वार्षिक

प्रवेश क्षमता वाला पाठ्यक्रम जिन सीटों के लिए धारा 10ए के तहत अनुमति दी गई थी भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (संक्षेप में "आईएमसी अधिनियम) केंद्र सरकार द्वारा. बाद में, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (संक्षेप में "एमसीआई") ने कॉलेज को पुरस्कार देने के लिए मान्यता प्रदान की एम.बी.बी.एस. एम.जे.पी. द्वारा दी गई डिग्री रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली, यू.पी. कॉलेज में स्नातकोत्तर की भी पढ़ाई होती है वर्ष 2011-12 के दौरान पाठ्यक्रम।

3. आईएमसी की धारा 10ए के तहत अनुमति दी गई थी वर्ष में 100 छात्रों के दूसरे बैच को प्रवेश देने हेतु अधिनियम 2007-08. बाद में कॉलेज ने इसके लिए आवेदन जमा किया 3 के प्रवेश हेतु अनुमति के नवीनीकरण की अवधि बढ़ाई गई एम.बी.बी.एस. की 100 सीटों का बैच। शैक्षणिक वर्ष 2008 के लिए- एमसीआई को 09. आवेदन पर कार्रवाई के बाद एम.सी.आई कॉलेज के निरीक्षण के लिए मेडिकल टीम गठित की. टीम ने 1 और 2 अप्रैल, 2008 को निरीक्षण किया इसके बाद एमसीआई टीम ने अपनी रिपोर्ट एमसीआई सचिव न्यू को सौंपी 02.04.2008 को दिल्ली। एमसीआई टीम ने निम्नलिखित बातें बताईं

एमसीआई विनियमों के अनुसार कॉलेज में कमियाँ: "शिक्षण संकाय की 21.05% (24) कमी थी 114 में से) और निवासी 37.03% (81 में से 30) जैसे अंतर्गत

(ए) प्रोफेसर - 4

(बी) एसोसिएट प्रोफेसर - 13

(सी) सहायक. प्रोफ़ेसर - 3

(डी) ट्यूटर-4

(ई) सीनियर रेजिडेंट - 16

(एफ) जूनियर रेजिडेंट - 14"

4. एमसीआई टीम ने ओपीडी अटेंडेंस पर भी गौर किया निरीक्षण की तिथि न्यूनतम के विरूद्ध मात्र 421 थी आवश्यकता 850-900 की थी और ओपीडी बिस्तर अधिभोग केवल था 83-85% की न्यूनतम आवश्यकता के मुकाबले 55%। एमसीआई बोर्ड विनियम के अनुसार टीम निरीक्षण रिपोर्ट थी को आयोजित बैठक में कार्यकारी समिति के समक्ष रखा गया 14.04.2008 और इसने केंद्र को अपना निर्णय सूचित किया के प्रवेश की अनुमति का नवीनीकरण सरकार नहीं करेगी वर्ष के शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रों का तीसरा बैच 2008-09, अपने पत्र दिनांक 16.04.2008 द्वारा। पत्र की एक प्रति काॅलेज के प्राचार्य को भी अनुरोध भेजा गया था बताई गई कमियों के संबंध में अनुपालन प्रस्तुत करें 30.04.2008 को या उससे पहले एमसीआई टीम द्वारा बाहर।

5. कॉलेज ने बाद में अपनी "अनुपालन रिपोर्ट" प्रस्तुत की। एमसीआई ने कॉलेज की जांच के लिए फिर से एक टीम गठित की

एमसीआई टीम द्वारा बताई गई कमियों को दूर कर लिया था। एमसीआई टीम ने 20.05.2008 को फिर से निरीक्षण किया और ने अपनी रिपोर्ट एमसीआई को सौंप दी है। रिपोर्ट में इस ओर इशारा किया गया है

निम्नलिखित कमियाँ:

"(1) शिक्षण संकाय की 18% (22) कमी थी

110 में से) और निवासियों को 5% (82 में से 5) निम्नानुसार:

(ए) प्रोफेसर - 6

(बी) एसोसिएट प्रोफेसर - 12

(सी) सहायक. प्रोफ़ेसर-4

(डी) ट्यूटर - शून्य

(ई) सीनियर रेजिडेंट - 3

(एफ) जूनियर रेजिडेंट - 2

(ii) निरीक्षण की तिथि पर ओपीडी उपस्थिति थी 850 की न्यूनतम आवश्यकता के मुकाबले केवल 691- 900.

(iii) आईपीडी बिस्तर अधिभोग इसके मुकाबले केवल 55(74%) था न्यूनतम आवश्यकता 83-95%।

6. बाद में एमसीआई निरीक्षण रिपोर्ट को सामने रखा गया एमसीआई की कार्यकारी समिति की 13/14-06 को हुई बैठक में- 2008

और समिति द्वारा नवीनीकरण न करने का निर्णय लिया गया के लिए छात्रों के तीसरे बैच के प्रवेश की अनुमति शैक्षणिक वर्ष 2008-09. कार्यकारी समिति का निर्णय केंद्र सरकार को अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था दिनांक 14.06.2008. तत्कालीन अवर सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय एवं परिवार कल्याण, नई दिल्ली ने 19.06.2008 को अग्रेषित किया एमसीआई से कॉलेज को पत्र प्राप्त कर जमा करने का अनुरोध किया गया है एमसीआई द्वारा बताई गई कमियों के संबंध में अनुपालन निरीक्षण दल. इसके बाद कॉलेज ने अनुपालन को आगे बढ़ाया अपने पत्र दिनांक 24.06.2008 द्वारा सचिव, एमसीआई को रिपोर्ट करें। कॉलेज ने दिनांक 01.07.2008 को एक और पत्र भी भेजा सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली जिसमें कहा गया है कि एमसीआई टीम ने जो कमियां बताई हैं मामूली प्रकृति का है और इसलिए, आवश्यक अनुदान देने का अनुरोध किया गया है तीसरे के प्रवेश हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अनुमति शैक्षणिक वर्ष 2008-09 के लिए बैच।

7. रोहोलहैंड मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष और हॉस्पिटल ने 03.07.2008 को स्वास्थ्य मंत्री को एक पत्र भेजा, भारत सरकार से आवश्यक अनुमति देने का अनुरोध और केंद्र सरकार, तीसरे बैच के प्रवेश के लिए, इसके बाद 04.07.2008 को सचिव को एक और पत्र लिखा गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।

8. मंत्री द्वारा प्राप्त पत्र के बाद हमने नोटिस किया साथ ही केंद्र सरकार के सचिव का गठन किया गया अनुपालन सत्यापन करने के लिए दो डॉक्टरों की एक टीम/ महाविद्यालय का निरीक्षण. केंद्रीय टीम ने संचालन किया दिनांक 11.07.2008 को सत्यापन निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, 10.07.2008 को नई दिल्ली।

केंद्रीय टीम ने बताया निम्नलिखित कमियाँ:

"(i) शिक्षण स्टाफ की कमी अधिक पाई गई

11% (116 में से 13) निम्नानुसार:

(ए) प्राध्यापक

(बी) एसोसिएट प्रोफेसर - 7

(सी) सहायक. प्रोफ़ेसर - 2

(डी) ट्यूटर - शून्य

(ई) सीनियर रेजिडेंट - 1

(एफ) जूनियर रेजिडेंट - 1

(ii) संकाय सदस्य एक ही पद पर थे अलग-अलग वेतन मिल रहा है. कुछ संकाय सदस्य रेजिडेंट डॉक्टरों से कम वेतन मिल रहा था। कुछ जूनियर रेजिडेंट्स की उम्र

अधिक थी। कुछ सीनियर रेजिडेंट्स ने अपना परिचय दिया ऐसा प्रतीत होता है कि घोषणा पत्र विशेषज्ञ बना रहे हैं निजी प्रैक्टिस, क्योंकि वे अधिकतर शहर में थे कॉलेज/संस्थान की स्थापना से पहले। कुछ क्षेत्र और भवन निर्माणाधीन थे, जो काम करने में उचित नहीं था क्षेत्र।"

9. तत्कालीन अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली ने दिनांक 27.07.2008 को कॉलेज के अध्यक्ष को एक पत्र भेजकर किसी भी नए प्रवेश को स्वीकार न करने का अनुरोध किया। शैक्षणिक वर्ष 2008-09 के लिए एमबीबीएस छात्रों का बैच। कॉलेज को भी कमियां सुधार कर भेजने की सलाह दी गयी शैक्षणिक वर्ष के लिए विचारार्थ अनुपालन रिपोर्ट आगे प्रवेश के लिए 2009-10।

10. कॉलेज के चेयरमैन ने तब एक रिट याचिका दायर की (सी) इस न्यायालय के समक्ष 2008 की संख्या 294 जिसे इसके साथ जोड़ दिया गया था अन्य समान रिट याचिकाएँ अन्य मेडिकल कॉलेजों द्वारा दायर की गईं। यह कोर्ट ने 03.09.2008 को एक आदेश पारित कर एमसीआई को निर्देश दिया अपनी सिफ़ारिशें केंद्र सरकार को प्रस्तुत करें दो दिन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय था के भीतर अनुमति प्रदान करने के मुद्दे पर विचार करने का निर्देश दिया सप्ताह। आगे यह भी निर्देशित

किया गया कि कॉलेज दिया जाए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुनवाई का अवसर और परिवार कल्याण, नई दिल्ली।

11. इस बीच, एमसीआई ने एक और आयोजन किया 19.08.2008 को एमसीआई टीम द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण एमसीआई सचिव को फिर से इंगित करते हुए अपनी रिपोर्ट सौंपी निम्नलिखित कमियाँ:

"(i) शिक्षण स्टाफ की कमी 2.3.68% पाई गई (114 में से 27):-

प्रोफ़ेसर - 3

एसोसिएट प्रोफेसर-13

सहायक प्रोफ़ेसर - 5

अध्यापक- 5

(ii) निवासी की कमी 20.9% पाई गई

(81 में से 17):-

सीनियर रेजिडेंट - 5

जूनियर रेजिडेंट - 12"

12. इसके बाद एमसीआई रिपोर्ट को कार्यकारिणी के समक्ष रखा गया समिति और एमसीआई ने 21.08.2008 को अपनी बैठक में, नवीनीकरण न करने के लिए केन्द्र सरकार को सूचित करने का निर्णय

लिया के लिए छात्रों के तीसरे बैच के प्रवेश की अनुमति शैक्षणिक वर्ष 2008-09. कार्यपालिका का निर्णय समिति को केंद्र सरकार को सूचित किया गया था इसका पत्र दिनांक 04.09.2008 पारित आदेश के संदर्भ में है इस न्यायालय द्वारा 03.09.2008 को रिट याचिका (सी) संख्या 294 वर्ष 2008 में, कॉलेज दायर किया

13. अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय इसके बाद कल्याण, नई दिल्ली ने दिनांक 09.09.2008 को एक पत्र भेजा उप सचिव के समक्ष पेश होंगे कॉलेज के चेयरमैन(चिकित्सा शिक्षा), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,अनुपालन रिपोर्ट सहित दिनांक 10.09.2008 को नई दिल्ली इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश में उल्लिखित अन्य दस्तावेज़ 03.09.2008 को. तभी कॉलेज के चेयरमैन उपस्थित हुए, निर्देशानुसार, 10.09.2008 को. अवर सचिव, मंत्रालय इसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, नई दिल्ली ने एक पत्र जारी किया कॉलेज के चेयरमैन ने विचार करने के बाद इसकी जानकारी दी कॉलेज द्वारा व्यक्तिगत समय पर प्रस्तुत किये गये तथ्य सुनवाई और एमसीआई की सिफारिशों के बाद यह निर्णय लिया गया मंत्रालय द्वारा प्रवेश के लिए अनुमति का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा शैक्षणिक वर्ष 2008-09 के लिए एमबीबीएस छात्रों के तीसरे बैच की-

14. कॉलेज के अध्यक्ष ने तब अपने दिनांकित पत्र द्वारा 12.09.2008, सचिव, चिकित्सा शिक्षा को संबोधित, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली ने उनसे अनुरोध किया एमबीबीएस के 50 विद्यार्थियों को शैक्षणिक अध्ययन की अनुमति प्रदान करना सत्र 2008-09. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली ने पुनः एक केन्द्रीय टीम का गठन कर प्रतिनियुक्ति की टीम को कॉलेज का निरीक्षण कर 25.09.2009 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है सकारात्मक रूप से. इसके बाद दोनों डॉक्टरों ने निरीक्षण किया कॉलेज 25.09.2008 को और रिपोर्ट 26.09.2008 को प्रस्तुत की गई उसी दिन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को। उस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने एक जारी किया पत्र दिनांक 26.09.2008 के अनुसार नवीनीकरण हेतु स्वीकृति के लिए 100 छात्रों के तीसरे बैच के प्रवेश की अनुमति शैक्षणिक वर्ष 2008-09

15. उक्त पत्र दिनांक 12.09.2008 की प्राप्ति पर कॉलेज के अध्यक्ष, अवर सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय एवं परिवार कल्याण को 24.09.2008 को एक पत्र लिखा सचिव, एमसीआई अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध कर रहे हैं सेवन कम करने के संबंध में. एमसीआई सचिव ने आपको सूचित किया एमसीआई द्वारा बताई गई कमियों के आधार पर दिनांक 19.08.2008 को महाविद्यालय के निरीक्षण के दौरान टीम कॉलेज में 50 के प्रवेश के लिए भी सुविधाओं का घोर अभाव था छात्र.

16. ऐसा देखा गया है कि एमसीआई टीम एक और गठित की गई है कमेटी कॉलेज का करेगी निरीक्षण 01.10.2008 और इस पर एमसीआई को एक रिपोर्ट सौंपी गई विभिन्न कमियों को उजागर करने का दिन रिपोर्ट सौंपी गई एमसीआई की कार्यकारी समिति की आयोजित बैठक में 06.10.2008 और समिति ने सूचित करने का निर्णय लिया केंद्र सरकार अनुमति का नवीनीकरण नहीं करेगी शैक्षणिक वर्ष 2008-09 और केंद्र सरकार से आग्रह करें को जारी दिनांक 26.09.2008 का अनुमति पत्र याद करें कॉलेज। एमसीआई की कार्यकारी समिति का फैसला केंद्र सरकार को अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था दिनांक 06.10.2008.

17. हमने देखा है कि केंद्र सरकार ने के लिए 100 छात्रों के तीसरे बैच को मंजूरी दी गई शैक्षणिक वर्ष 2008-09 26.09.2008 को, बार-बार दोहराए जाने के बावजूद एमसीआई द्वारा और उससे पहले की गई नकारात्मक सिफारिशें 26.09.2008 को एमसीआई ने अनुमति भी नहीं दी परामर्श किया. हमने स्थिति को दर्शाने के लिए तथ्यों का संकेत दिया है जो वर्ष 2008-09 में प्रचलित था और जिस प्रकार से द्वारा 100 विद्यार्थियों के प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई केंद्र सरकार।

18. एमसीआई ने 04.06.2013 को लिए गए अपने निर्णय का पालन करते हुए, ने अपने पत्र दिनांक 20.06.2013 द्वारा अपनी स्वीकृति संप्रेषित करने का निर्णय लिया द्वितीय बैच में प्रवेश हेतु अनुमति के

नवीनीकरण हेतु बढ़ी हुई संख्या के मुकाबले एमबीबीएस छात्रों की संख्या यानी 100 से शैक्षणिक वर्ष 2013-14 के लिए कॉलेज में 150 सीटें। को ध्यान में रखते हुए मंजूरी प्रदान की गई मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांक 26/27-02-2013 को प्रस्तुत की गई एमसीआई का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कुछ शर्तों के अधीन है यहां नीचे निकाले गए हैं: "मुझे यह सूचित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि आपको और आपके संस्थान को सहित मानदंडों को पूरा करने और बनाए रखने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं बुनियादी ढाँचा, भौतिक और मानव संसाधन दोनों, संपूर्ण शिक्षण संकाय और नैदानिक सामग्री इत्यादि शैक्षणिक वर्ष, जैसा कि मेडिकल के विनियमन में निर्धारित है भारतीय परिषद. झूठी/गलत घोषणा के मामले में या खरीद के लिए मनगढ़ंत दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया है वृद्धि के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अनुमति सेवन और उक्त कदाचार को ध्यान में लाया जाता है या के दौरान किसी भी स्तर पर एमसीआई का ज्ञान प्राप्त होता है वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में, आपका संस्थान उत्तरदायी नहीं है वृद्धि के विरूद्ध अनुमति के नवीनीकरण हेतु विचार किया गया अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश और इसका नवीनीकरण अगले के लिए बढ़े हुए सेवन के विरुद्ध अनुमति शैक्षणिक वर्ष और इसके विरुद्ध अनुमति का नवीनीकरण बढ़ा हुआ सेवन भी वर्तमान के लिए रद्द किया जा सकता है शैक्षणिक वर्ष। इसके अलावा एमसीआई को यह सब लेने का अधिकार है आपके और आपके कॉलेज/संस्थान के विरुद्ध उपाय कानून के तहत अनुमति है।"

19. इसी बीच एमसीआई को एक गोपनीय पत्र मिला केंद्रीय जांच ब्यूरो से दिनांक 11.07.2013 (के लिए)

संक्षेप में "सीबीआई") यह सूचित करते हुए कि सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है कॉलेज के चेयरमैन और मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ धारा 120बी के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नई दिल्ली आईपीसी और धारा 13(2) को धारा 13(1)(डी) के साथ पढ़ा जाए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संक्षेप में "पीसी अधिनियम")। पत्र के साथ आरोप पत्र भी संलग्न था, जो में एमसीआई के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के समक्ष रखा गया था बैठक दिनांक 12.07.2013 को आयोजित की गई। इसके बाद बोर्ड ने इसे रद्द कर दिया दिनांक 04.06.2013 के निर्णय से भूमि को सूचित किया गया कॉलेज ने अपने पत्र दिनांक 20.06.2013 द्वारा। का बोर्ड एमसीआई के गवर्नरों ने कॉलेज को सूचित किया कि पत्र द्वितीय के प्रवेश नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की गई। बैच छात्रों की आयु में वृद्धि हुई प्रवेश संख्या यानी 100 से 150 तक acaden.ic वर्ष 2013-14 के लिए रद्द कर दिया जाएगा तत्काल प्रभाव

20. जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है, उस निर्णय की वैधता है इस रिट याचिका में विचार के लिए जो मुख्य मुद्दा उठता है।

21. श्री मुकुल रोहतगी, उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पत्र दिनांक 13.07.2013 है वृद्धि के लिए प्रवेश हेतु दी गई

अनुमति को निरस्त करना सेवन दुर्भावनापूर्ण था और प्राकृतिक सिद्धांतों का उल्लंघन था न्याय। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि एक अधिकार है निर्णय के आधार पर याचिकाकर्ताओं को पहले ही अर्जित किया जा चुका है एमसीआई द्वारा 04.06.2013 को लिया गया, जिसकी सूचना दी गई कॉलेज ने अपने पत्र दिनांक 20.06.2013 द्वारा। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि ऐसा निर्णय वैध रूप से लिया गया था निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 26/27.02.2013. विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत किया गया कि चूंकि कॉलेज ने सभी का अनुपालन किया है विनियमों में निर्धारित शर्तें और ऐसा नहीं है कमी, जैसा कि निरीक्षण दल द्वारा बताया गया है, कोई नहीं है पहले से दी गई अनुमति को भी रद्द करने का औचित्य याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर दिए बिना। विद्वान वरिष्ठ वकील ने भी यह तथ्य प्रस्तुत किया कि सीबीआई ने मंत्रालय के कुछ अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नई दिल्ली एवं इसके विरूद्ध भी कॉलेज का चेयरमैन इसे रद्द करने का बिल्कुल भी आधार नहीं है छात्रों के अतिरिक्त प्रवेश के लिए अनुमति पहले ही दी जा चुकी है शैक्षणिक वर्ष 2013-14 के लिए चूंकि कॉलेज संतुष्ट है स्थापना के विनियमों के अंतर्गत सभी आवश्यकताएँ मेडिकल कॉलेज विनियम, 1999 के विद्वान वरिष्ठ वकील यह भी कहा कि भले ही कॉलेज के चेयरमैन हों आरोप पत्र दायर किया गया है, वह स्वयं रद्द करने का आधार नहीं है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा दिया गया अनुमति पत्र, जब तक कि उसे

सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी न ठहराया गया हो आपराधिक जांच में क्षेत्राधिकार. विद्वान वरिष्ठ वकील "के संवर्द्धन" के विनियम 3(5) का संदर्भ दिया मेडिकल में स्नातक पाठ्यक्रमों में वार्षिक प्रवेश क्षमता महाविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2013-14 हेतु केवल विनियम, 2013 (संक्षेप में "विनियमन 2013)।

22. छात्रों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अमरेंद्र शरण ने कहा कि के आधार पर एमसीआई के दिनांक 20.06.2013 के निर्णय से 21 छात्रों को 10 जुलाई, 2013 तक कॉलेज में प्रवेश प्राप्त कर लिया, चूंकि उन्हें सफलतापूर्वक कॉलेज आवंटित किया गया था यूपी से मुकाबला संयुक्त मेडिकल प्रवेश परीक्षा (संक्षेप में) "यूपीसीएमईटी) और एमसीआई द्वारा लिया गया निर्णय 13.07.2013 के अब तक गंभीर परिणाम होंगे छात्र चिंतित हैं क्योंकि वे प्राप्त नहीं कर पाएंगे इस शैक्षणिक वर्ष के लिए किसी अन्य निजी संस्थान में प्रवेश। विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि कॉलेज ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अनुसार सुविधा प्रदान की गई विनियम और अनुमति न देने का कोई औचित्य नहीं है छात्रों को कॉलेज में अपनी पढ़ाई जारी रखनी होगी भले ही वे वहां हों द्वारा दी गई अनुमति प्रदान करने में कुछ त्रुटि थी वर्ष के दौरान अतिरिक्त सेवन के लिए केंद्र सरकार 2008-09.

23. श्री अमित कुमार, विद्वान वकील उपस्थित हुए दूसरी ओर, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने फैसले को सही ठहराया है एमसीआई द्वारा 13.07.2013 को लिया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया कि एमसीआई के पास अपने पहले लिए गए निर्णय को रद्द करने की शक्ति है 04.06.2013 को यदि पर्याप्त सामग्री लायी गयी हो ज्ञान जिसका इस मामले में बहुत महत्व है महाविद्यालय में पाठ्यक्रमों का संचालन। विद्वान परामर्श भी दिनांक 20.06.2013 के पत्र को प्रस्तुत एवं संदर्भित किया गया बताया गया कि अनुमति कुछ शर्तों के अधीन दी गई थी शर्तों और उन शर्तों का उल्लंघन किया गया है कॉलेज। विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि धारा के अनुसार चिकित्सा विनियमों की स्थापना के 8(3)(1)(डी)। (संशोधन 2010 भाग II), एमसीआई को ऐसा न करने की शक्ति मिल गई है यदि बाद में ऐसा प्रतीत हो तो अनुमति/मान्यता नवीनीकृत करें यह पाया गया है कि संस्थान ने फर्जी/जाली दस्तावेजों पर कार्य किया है किसी संस्थान को अनुमति के नवीनीकरण के लिए विचार नहीं किया जा सकता/ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए दो वर्षों के लिए मान्यता शैक्षणिक वर्ष और अगला शैक्षणिक वर्ष भी। इस तरह, एमसीआई ने अनुमति पत्र रद्द करते हुए लिया फैसला द्वितीय बैच के विद्यार्थियों के प्रवेश नवीनीकरण हेतु अकादमिक के लिए विद्यार्थियों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दी गई वर्ष 2013-14 को उचित ठहराया गया।

24. हम अभूतपूर्व वृद्धि को लेकर चिंतित हैं इस देश में तकनीकी और चिकित्सा संस्थानों की जो जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न अनैतिकताओं का व्यापक प्रसार हुआ है अभ्यास. कैपिटेशन शुल्क के माध्यम से बड़ी राशि का संग्रहण एमबीबीएस और पोस्ट-ग्रेजुएट के लिए करोड़ों रुपये चल रहे हैं ऐसे कई लोगों द्वारा सीटें, अत्यधिक शुल्क, दान आदि वित्तीय संस्थानों ने मेधावी लोगों को आर्थिक रूप से गरीब बनाए रखा है छात्र उन संस्थानों से दूर हैं। दबाव तो ये भी दिखता है, अतिरिक्त के लिए, विभिन्न संस्थानों द्वारा बढ़ाया जा रहा है छात्रों का प्रवेश, हमेशा छात्र के लाभ के लिए नहीं समुदाय की सेवा करें और इस प्रकार समुदाय की सेवा करें, लेकिन अपने स्वयं के लिए बेहतरी.

25. हम स्वीकार्यता पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, या अन्यथा मंत्री पर जो आरोप लगे हैं. नौकरशाह या कॉलेज के अध्यक्ष। लेकिन तथ्य बनी हुई है, इसके बाद सी.बी.आई. को जांच करनी पड़ी उन पर धारा 120 बी, 468, 471 आईपीसी और के तहत आरोप पत्र दाखिल करें धारा 13(2) पीसी अधिनियम की धारा 13(1)(डी) के साथ पठित। सीबीएल जांच से प्रथम दृष्टया आपराधिक साजिश की पुष्टि होती है कॉलेज के चेयरमैन और तत्कालीन यूनियन के बीच स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार, तत्कालीन उप सचिव, मंत्रालय के साथ नई दिल्ली स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, नई दिल्ली, दो डॉक्टर, एक हैं नेफ्रोलॉजी वीएमएमवी और

सफदरजंग अस्पताल के प्रमुख और अन्य सामुदायिक चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर हैं, वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली जो नेतृत्व करते हैं 50 के अतिरिक्त सेवन हेतु पारित आदेश जारी करना 26.09.2008 को शैक्षणिक वर्ष 2008-09 के लिए छात्र। के लिए दोनों डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पूर्व अनुमति जरूरी सीबीआई द्वारा सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया गया था।

26. सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में गंभीर बातें बताई हैं केंद्रीय टीम द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में खामियां, जो दिनांक 25.09.2008 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया, जो इस प्रकार हैं: "उपरोक्त चार्ट स्पष्ट रूप से साबित करता है कि आरोपी डॉ. विंदू है इसमें अमिताभ और आरोपी डॉ. एस.के.रसानिया पक्षकार थे बड़ी साजिश और वे जानबूझकर सीमित कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट में फैकल्टी की कमी 2% बताई गई है; चमका दिया था संकाय की ताकत में स्पष्ट कमियों पर सदस्य (15% यानी 115 में से 17) और इस प्रकार, सुविधा हुई केंद्र की अनुमति लेने में निजी कॉलेज सरकार.आपराधिक साजिश में इनकी संलिप्तता और भी अधिक है इस तथ्य से स्थापित किया गया कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने ऐसा कियासंकाय सदस्यों से यह न पूछें कि क्या वे (संकाय) सदस्य) पूर्णकालिक या अंशकालिक/केवल बुलाए गए थे निरीक्षण के उद्देश्य से सदस्य बनायें। जांच से पता चला है कि कम से कम 5 डॉक्टर, अर्थात्, डॉ. हरबीर सिंह सोढ़ी,

डॉ. अनिल मदान, डॉ. बीरेंद्र कुमार सिन्हा, डॉ. जमालुद्दीन और डॉ. शिव नाथ बनर्जी, जिन्हें पूर्णकालिक संकाय के रूप में दिखाया गया है रोहिलखंड के अभिलेखों में सदस्य और निवासी 2008 के दौरान मेडिकल कॉलेज, बरेली ने इसकी पुष्टि की है उन्होंने उक्त कॉलेज में कभी भी पूर्णकालिक के रूप में काम नहीं किया था 2008 के दौरान, बल्कि विजिटिंग फैकल्टी थे। ये तथ्य आरोपी डॉ. विंदू की निरीक्षण रिपोर्ट साबित करें अमिताभ और आरोपी डॉ. एस.के. रसानिया निपुण थे और निजी मेडिकल कॉलेज के पक्ष में पक्षपात किया। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी डाॅ. विंदू अमिताभ और आरोपी डॉ. एस.के. रसानिया के पास है वार्डों का व्यक्तिगत निरीक्षण करने का दावा किया विभाग. उन्होंने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है कि सभी की ओपीडी में मरीजों की उपस्थिति (विभाग अच्छे थे, बिस्तर अधिभोग के बारे में था 90% और आईसीयू अपनी क्षमता से भरा हुआ था। तथापि, जांच के दौरान 14 मरीजों का भौतिक सत्यापन किया गया. जिन्हें ओपीडी रजिस्टर में तिथि पर उपस्थित दर्शाया गया था का निरीक्षण, अर्थात 25.09.2003 को आयोजित किया गया था डाक विभाग. यादृच्छिक आधार पर. इस बात का खुलासा हुआ उनमें से 09 नकली या अस्तित्वहीन थे। का दावा केंद्रीय टीम के डॉक्टरों पर ऐसा करने का आरोप लगाया वार्डों और विभागों का व्यक्तिगत निरीक्षण, जो कि एक महत्वपूर्ण मानदंड था, के आधार पर जिसे उन्होंने कॉलेज को हरी झंडी दे दी और इस प्रकार बदल गया गुण और मिथ्या से

रहित होना। जांच से यह भी पता चला कि सेंट्रल टीम में आरोपी डॉ. विंदू अमिताभ और शामिल हैं आरोपी डॉ. एस.के. रसानिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि घोषणा पत्र की फोटोकॉपी स्वीकार की, सत्यापन हेतु एमसीआई को प्रस्तुत किया गया। जांच के दौरान मो. यह पता चला है कि घोषणा पत्र उपलब्ध कराए गए हैं संबंधित कॉलेज द्वारा, सभी संकाय का विवरण शामिल करें सदस्य, उनकी शैक्षणिक योग्यता, नियुक्ति पत्र, पहचान दस्तावेज (जैसे पैन कार्ड, आदि) मेडिकल में उनके निवास के समर्थन में दस्तावेज़ कॉलेज (राशन कार्ड की तरह, अपने अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए) वहां स्थायी संकाय सदस्य)। जांच के दौरान, 5 तथाकथित संकाय सदस्य (डॉ. हरबीर सिंह सोढ़ी, डॉ. अनिल मदान, डॉ. बीरेंद्र कुमार सिन्हा, डॉ. जमालुद्दीन और डॉ. शिव नाथ बनर्जी) कहा है कि उन्हें सिर्फ इसलिए बुलाया जाता था उक्त महाविद्यालय का निरीक्षण। वे सर्वोत्तम स्थिति में थे, दौरा कर रहे थे विश्वविद्यालय के विभाग के सदस्य। संयोग से, एमसीआई के नियमों में ऐसा नहीं है अंशकालिक या अतिथि संकाय सदस्यों के लिए प्रावधान। हालांकि उक्त पांच डॉक्टरों ने अपने हस्ताक्षर कर रखे हैं उन्होंने अपने घोषणा पत्र प्राप्त करने से इनकार कर दिया है नियुक्ति पत्र उनके साथ संलग्न दिखाए गए हैं संबंधित घोषणा प्रपत्र. उन्होंने यह भी कहा है राशन कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, फॉर्म -16 (आय)। कर) आदि उनके नाम से जारी होना दर्शाया गया था उन्हें कभी नहीं दिया गया. इसके अलावा, यह पाया गया है कि वे सभी फर्जी/नकली और जाली हैं, जैसे वे

(डॉक्टर) थे न ही अभिलेखों में दर्शाए गए पते पर निवासी क्या उन्होंने कभी किसी राशन कार्ड के लिए आवेदन किया था। जिला पूर्ति अधिकारी बरेली ने इन्हें जारी करने से इंकार कर दिया है पुष्टि की गई कि उक्त राशन कार्ड फर्जी एवं जाली हैं। गौरतलब है कि फर्जी राशन कार्ड हैं कॉलेज अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया गया एमसीआई इंस्पेक्टरों के सामने कहा कि डॉक्टर उनके हैं स्थायी संकाय सदस्य. इसी तरह कोई फॉर्म-16 भी नहीं था कॉलेज द्वारा उन्हें कभी भी जारी किया गया। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि मामले में उक्त डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए कॉलेज प्राधिकारियों द्वारा उनके नाम के बिना जानकारी और नियुक्तियों का ब्यौरा तक नहीं के डॉक्टरों/कर्मचारियों के हस्ताक्षर हों स्वीकार्य कॉलम में कॉलेज. इससे यह सिद्ध होता है कॉलेज द्वारा (जाली) दस्तावेजों का निर्माण और उपयोग अधिकारियों की मंजूरी प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार. एमसीआई/सेंट्रल की सिफारिशों पर भारत की भारत सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त टीम। हालाँकि, आरोपी डॉक्टर यानी... डॉ. विंदू अमिताभ और डॉ. एस.के. मध्य के रसानिया आपराधिक साजिश के अनुसरण में टीम ने ऐसा नहीं किया द्वारा लगाए गए दस्तावेजों की सत्यता की पुष्टि करें कॉलेज के अधिकारियों और दस्तावेजों को सत्यापित किए बिना घोषणा प्रपत्रों की फोटोप्रतियाँ स्वीकार की गईं पर कॉलेज के पक्ष में सकारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की अगले ही दिन। इसके बावजूद यह उल्लेख करना उचित है ऐसे डॉक्टरों की उपस्थिति

का उल्लेख करते हुए, जो थे यहां तक कि बरेली में प्रैक्टिस भी की और इसका प्रोडक्शन भी नहीं हुआ मूल नियुक्ति पत्र मांगे जाने पर भी ऐसा कहा गया केंद्रीय टीम फिर भी क्लीन चिट देने के लिए आगे बढ़ी कॉलेज। "

27. हम इस तथ्य का न्यायिक नोटिस भी ले सकते हैं कि कई कई बार मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज और द्वारा बड़ी रकम हड़प कर अन्य स्थापित किये जा रहे हैं वित्तीय संस्थानों से ऋण और अन्य उधार लेने का तरीका, अपने स्वयं के धन के बिना, और एक बार कॉलेज को मंजूरी मिल जाती है और छात्रों को प्रवेश दिया जाता है, लिया गया ऋण चुकाया जा रहा है छात्रों से ली जाने वाली कैपिटेशन फीस और अंततः वह राशि उनकी पूंजी बनती है। कई बार तो बिना किसी के भी पर्याप्त सुविधाओं के कारण वे विभिन्न एजेंसियों पर दबाव डालते हैं और केंद्र सरकार की अनदेखी कर अनुमोदन प्राप्त करें एमसीआई जैसी नियामक प्राधिकरण, जो गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है इस देश में चिकित्सा शिक्षा की. उदाहरण के लिए, एमसीआई ने तत्काल मामले में एक सुसंगत दृष्टिकोण लिया गया और नकारात्मक भेजा गया केंद्र सरकार को रिपोर्ट करती है, लेकिन सब कुछ नजरअंदाज कर देती है एमसीआई द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार को ए अपनी स्वयं की रिपोर्ट और दिनांकित पत्र द्वारा अनुमति प्रदान की गई 26.09.2008. सीबीआई ने

अपनी चार्जशीट में स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से बताया गया कि यह फर्जी, फर्जी के आधार पर किया गया है और जाली रिकॉर्ड. सीबीआई ने देखा कि कॉलेज अधिकारियों ने ऐसा किया था के समक्ष मनगढ़ंत एवं जाली दस्तावेज प्रस्तुत किये निरीक्षण दल और टीम सत्यता की जांच करने में विफल रही या अन्यथा उन दस्तावेज़ों का. सीबीआई जांच हो चुकी है पता चला कि केंद्रीय टीम द्वारा धोखाधड़ी का अभ्यास किया गया है साथ ही कॉलेज को तीसरे बैच की मंजूरी मिलनी हैशैक्षणिक वर्ष 2008-09 के लिए एमबीबीएस छात्र।निरीक्षण दल का कर्तव्य:

28. मेडिकल काउंसिल अधिनियम, 1956, विशेष रूप से धारा 1 ओए, शासनादेश है कि जब कोई नया मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाना है या सीटों की संख्या बढ़ाई जानी है, इसकी अनुमति केंद्र सरकार एक पूर्व शर्त है. धारा 19ए बाध्य करती है एमसीआई चिकित्सा के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक निर्धारित करेगी शिक्षा और एमसीआई द्वारा की गई सिफारिश केंद्र सरकार का काफी महत्व है, यह एक है विशेषज्ञ निकाय. एमसीआई ने विनियमन निर्धारित किया था - "न्यूनतम 100 के लिए मेडिकल कॉलेज के लिए मानक आवश्यकताएँ प्रवेश वार्षिक विनियम, 1999" जो कि प्रासंगिक है हमारा मामला, दिनांक 29.1.2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। न्यूनतम आवश्यकताओं को सत्यापित करने के लिए, एमसीआई को मिलता है निरीक्षकों द्वारा किया गया

निरीक्षण, जो विशेषज्ञ हैं, प्रस्तुत करते हैं स्टाफ की उपलब्धता पर उनकी रिपोर्ट - शिक्षण औरनिवासी - और अन्य बुनियादी सुविधाएं, नैदानिक उपलब्धता, आदि नियमों के अनुसार।

29. हम देखते हैं, इस मामले में, सभी अवसरों पर, एमसीआई टीम ने सेंट्रल को अनुशंसा करने का निर्णय लिया सरकार तीसरे के प्रवेश की अनुमति का नवीनीकरण नहीं करेगी शैक्षणिक वर्ष 2008-09 के लिए बैच। का लगातार रुख एमसीआई ने विभिन्न मुद्दों पर केंद्र सरकार को सूचित किया था अवसरों पर, लेकिन उनके दृष्टिकोण का पता लगाए बिना, एक केंद्रीय टीम नियुक्त की गई, अनुकूल रिपोर्ट और अनुमति मिली वर्ष 2008 के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया था- 09 जो कि सी.बी.आई जांच का विषय था।

30. अब हमें निर्णय की वैधता की जांच करनी है उपरोक्त तथ्यात्मक एवं के आलोक में दिनांक 13.07.2013 को एम.सी.आई कानूनी परिदृश्य. हमने पहले ही संकेत दे दिया है कि मंजूरी कब मिलेगी 20.06.2013 को प्रदान किया गया था, यह स्पष्ट रूप से कहा गया था एमसीआई ने कहा कि कुछ शर्तों के अधीन यह अनुमति दी गई है। उसमें कहा गया था कि झूठी/गलत घोषणा के मामले में या अनुमति प्राप्त करने के लिए मनगढ़ंत दस्तावेजों का उपयोग किया गया है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बढ़े हुए सेवन और यदि कहा जाए तो कदाचार को ध्यान में लाया गया या सामने आया

वर्तमान शैक्षणिक के दौरान किसी भी स्तर पर एमसीआई का ज्ञान वर्ष (2013-14) संस्थान/कॉलेज उत्तरदायी नहीं होगा वृद्धि के विरूद्ध अनुमति के नवीनीकरण हेतु विचार किया गया अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश और उसका नवीनीकरण शैक्षणिक वर्ष के लिए बढ़े हुए प्रवेश के विरुद्ध अनुमति 2013-14 और अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए भी ऐसा ही होगा निरस्त किये जाने योग्य होगा।

31.सीबीआई का पत्र भी प्राप्त हुआ है आक्षेपित आदेश दिनांक 13.07.2013 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था एमसीआई द्वारा दिए गए अनुमति पत्र को रद्द करते हुए जारी किया गया शैक्षणिक वर्ष 2013-14.

32. हमारा मानना है कि उपरोक्त निर्णय लिया गया है एमसीआई मेडिकल की स्थापना के अनुरूप है कॉलेज विनियमन (संशोधन 2010 भाग II)। उपरोक्त- उल्लिखित विनियमन एमसीआई द्वारा इसके अभ्यास में जारी किया गया था पिछले के साथ आई एमसी अधिनियम, 1956 की धारा 33 के तहत शक्तियां केंद्र सरकार की मंजूरी. का खंड 8.3 विनियमन अनुमति प्रदान करने, उप-खंड से संबंधित है8(3)(1)(डी) उन कॉलेजों से संबंधित है जो पाए जाते हैं फर्जी/फर्जी दस्तावेजों से नियोजित शिक्षक। वे प्रावधान यहां नीचे निकाले गए हैं: "8(3)(1)(डी) जिन महाविद्यालयों में रोजगार पाया गया है फर्जी/जाली दस्तावेजों वाले शिक्षक: यदि देखा जाए तो कोई

भी संस्थान नियोजित पाया जाता ह एक शिक्षक के पास फर्जी/फर्जी दस्तावेज हैं ऐसे शिक्षक का घोषणा पत्र जमा किया, जैसे किसी संस्थान के नवीनीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा एम.बी.बी.एस. पुरस्कार हेतु अनुमति/मान्यता डिग्री/ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए आवेदनों का प्रसंस्करण दो शैक्षणिक वर्ष - अर्थात वह शैक्षणिक वर्ष और वह अगला शैक्षणिक वर्ष भी. हालाँकि, परिषद का कार्यालय यह सुनिश्चित करेगा तक कम से कम 3 दिन पहले निरीक्षण नहीं किया जाता है महत्वपूर्ण धार्मिक और त्यौहार की छुट्टियों के 3 दिन बाद केंद्र/राज्य सरकार द्वारा घोषित।"

33. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील, पहले से ही संकेत दिया, प्रस्तुत किया कि केवल तभी जब महाविद्यालय का अध्यक्ष हो किसी अपराधी में सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया जांच के बाद ही दी गई मंजूरी रद्द की जा सकेगी। ऐसा तर्क 2013 के विनियमों के आधार पर उठाया गया था, जो हमारे विचार में, इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा। विनियम 2013 का विनियम 3 इस प्रकार है:"3. आवेदन करने की पात्रता:

(1) आवेदन मौजूदा में वार्षिक सेवन क्षमता को बढ़ाने के लिए मान्यता से बन सकेंगे मेडिकल कॉलेज के बोर्ड को मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है भारतीय चिकित्सा परिषद के अधिक्रमण में राज्यपाल।

सरकारी एवं गैर सरकारी के लिए आवेदन का प्रारूप सरकारी स्वामित्व वाला मेडिकल कॉलेज निर्धारित है अनुसूची । इन विनियमों से जुड़ी हुई है।

(2) केवल ऐसे मौजूदा मेडिकल कॉलेज ही पात्र होंगे इन विनियमों के तहत आवेदन करने के लिए न्यूनतम दस का आनंद लें प्रारंभिक पत्र के अनुदान की तारीख से खड़े होने के वर्ष केंद्र सरकार और एमबीबीएस द्वारा अनुमति उनके द्वारा प्रदान की गई योग्यता प्रथम में शामिल है भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (अधिनियम) की अनुसूची 1956 का क्रमांक 102)।

(3) 50 या वार्षिक प्रवेश वाले मेडिकल कॉलेज अधिक लेकिन 100 से कम एमबीबीएस सीटों पर आवेदन करने के पात्र होंगे वार्षिक सेवन क्षमता को एक बार के रूप में 100 तक बढ़ाने के लिए उपाय।

(4) 100 या की वार्षिक प्रवेश संख्या वाले मेडिकल कॉलेज अधिक लेकिन 150 एमबीबीएस सीटों से कम सीटें आवेदन के लिए पात्र होंगी वार्षिक सेवन क्षमता को 150 तक बढ़ाने के लिए, एक के रूप में- समय माप.

(5) ऐसे मेडिकल कॉलेज जिन्हें अनुमति नहीं दी गई हैसुपर में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा अनुमति पत्र

भारतीय चिकित्सा परिषद के सत्र के अनुसार मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की धारा 8(1)(3)(डी). विनियम, 1999 (आधिकारिक राजपत्र में

अधिसूचित)। 16.04.2010) और/या वह व्यक्ति जिसने इसकी स्थापना की है की एक अदालत ने मेडिकल कॉलेज को दोषी ठहराया है आपराधिक जांच में सक्षम क्षेत्राधिकार शुरू किया गया केंद्रीय जांच ब्यूरो या पुलिस द्वारा।"

34. विनियम 3 के खंड (2) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल ऐसे मेडिकल कॉलेज इन विनियमों के तहत पात्र होंगे अनुदान की तारीख से कम से कम 10 वर्ष की अवधि का अनुभव प्राप्त करें केंद्र सरकार द्वारा अनुमति का प्रारंभिक पत्र। अभी तक जहां तक याचिकाकर्ता का संबंध है, उन्होंने केवल आठ ही पूरे किए हैं वर्ष, परिणामस्वरूप, विनियम 2013 उन पर लागू नहीं होगा।

35. याचिकाकर्ताओं की स्थापना द्वारा शासित हैं मेडिकल कॉलेज विनियम, (संशोधन), 2010 (भाग II), विशेषकर खंड 8(3)(1)(डी), जिसकी स्थिति में जब एम.आई.सी पाया गया कि कॉलेज ने फर्जी/जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है आवेदनों पर कार्रवाई के लिए अनुमति/मान्यता का नवीनीकरण इत्यादि के अभाव में उस संस्थान पर नवीनीकरण हेतु विचार नहीं किया जा सकेगा एमबीबीएस डिग्री प्रदान करने के लिए अनुमति/मान्यता की/ दो के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन पर कार्रवाई शैक्षणिक वर्ष अर्थात वह शैक्षणिक वर्ष और अगला शैक्षणिक वर्ष वर्ष। इस मामले में दिनांक 11.07.2013 को सी.बी.आई. का पत्र प्राप्त

हुआ एमसीआई और इसे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के समक्ष रखा गया था 12.07 .2013 को निरस्तीकरण आदेश पारित किया गया 13.07 .2013 द्वितीय के लिए अनुमति के नवीनीकरण को रद्द करना 100 से 150 तक बढ़ाए गए प्रवेश के विरुद्ध छात्रों का बैच शैक्षणिक वर्ष 2013-14 के लिए छात्र।

36. हमारा मानना है कि एमसीआई को इसकी आवश्यकता नहीं है के आधार पर शुरू किए गए मुकदमे की परिणति तक प्रतीक्षा करें सीबीआई द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट. एक प्रधान मंत्री द्वारा जांच सीबीआई जैसी एजेंसी ने प्रथमदृष्टया खुलासा किया है कि कॉलेज की मंजूरी पाने के लिए नकली और जाली सामग्री का इस्तेमाल किया है हमारे विचार से, वर्ष 2008-09 के लिए यह पर्याप्त है एमसीआई विनियम 8(1)(3)(डी) के अनुसार कार्रवाई करेगी विनियम 2013 के.

37. हम भी उठाए गए तर्क से प्रभावित नहीं हैं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अमरेन्द्र शरण छात्र कि वे 10.07.2013 को पाठ्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। UPCMET द्वारा जारी सूचना विवरणिका दो का उल्लेख करती है महत्वपूर्ण तिथियाँ। महत्वपूर्ण तिथियां परिणाम की तिथि हैं15.06.2013 की घोषणा और उसके बाद काउंसलिंग शुरू होगी 15.07 .2013. यदि ऐसा है, तो हम यह देखने में असफल हो जाते हैं कि छात्र कैसे हो सकते हैं 10.07.2013 को भर्ती कराया गया। हालाँकि, वकील ने संदर्भ दिया 'दैनिक जागरण' अखबार को जहां इस बात की ओर इशारा

किया गया है पहली काउंसलिंग 5 जुलाई 2013 को होगी, हम नहीं दे सकते सूचना की तुलना में समाचार आइटम की पवित्रता टीसी यूपी द्वारा प्रकाशित ब्रोशर गैर सहायता प्राप्त मेडिकल कॉलेज UPCMET के संचालन के लिए वेलफेयर एसोसिएशन। यहां तक की अन्यथा, हमारे विचार में, एक बार मेडिकल काउंसिल को पता चल जाता है कि फर्जी एवं कूटरचना के आधार पर स्वीकृति प्राप्त की गई थी दस्तावेज़, खंड 8(3)(1)(डी) लागू होता है और धोखाधड़ी उजागर होती है सब कुछ। हम यह स्पष्ट करते हैं कि आपराधिक मामले का आरोप- हालाँकि, सीबीआई द्वारा दायर मामले का निपटारा बिना किसी प्रभाव के किया जाएगा इस निर्णय में हमारे द्वारा की गई टिप्पणियों, यदि कोई हो, द्वारा।

न्यायालय की चिंता

38. हम सोचते हैं, यह विचार करने का एक उपयुक्त अवसर है क्या हमने वाक्चातुर्य से वांछित लक्ष्य प्राप्त कर लिये हैं इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णयों पर प्रकाश डाला गया टी.एम.ए. में पाई फाउंडेशन और अन्य बनाम कामताका राज्य और अन्य (2002) 8 एससीसी 481 और पी.ए. एलनामदार और अन्य वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2005) 6 एससीसी 537. टीएमए पाई फाउंडेशन केस (सुप्रा) में कहा गया है कि कुछ भी गलत नहीं है यदि प्रवेश परीक्षा स्व-वित्तीय संस्थानों द्वारा या द्वारा आयोजित की जा रही है संस्थानों का एक समूह लेकिन उन्हें प्रवेश परीक्षा

आयोजित करनी चाहिए निष्पक्ष, पारदर्शी और निष्पक्ष होने की तिहरी कसौटी पर खरे उतरें शोषणकारी. टीएमए पाई फाउंडेशन (सुप्रा) और /नामदार (सुप्रा) बार-बार कहा गया कि शैक्षिक स्थापना का उद्देश्य संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना और शिक्षा प्रदान करना नहीं है स्वभाव से परोपकारी. कोर्ट ने बार-बार कहा है कि आम निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा mu•3t के दोहरे उद्देश्य की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक होना चाहिए पारदर्शिता और योग्यता और कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा मुनाफाखोरी नहीं होनी चाहिए. हालाँकि, तथ्य इसके विपरीत हैं चित्र। एलनामदार में, इस न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है घोषित किया गया कि कोई कैपिटेशन शुल्क वसूलने की अनुमति नहीं दी जाएगी का भुगतान करके किसी भी सीट को विनियोजित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती कैपिटेशन शुल्क.

39. हालाँकि, सीबीएल की जाँच से एक खेदजनक स्थिति का पता चलता है मामलों का, जो उचित कदम उठाने के लिए आंखें खोलने वाला है भविष्य में उपचारात्मक उपाय ताकि चिकित्सा शिक्षा हो सके आईएमसी अधिनियम और विनियमों द्वारा परिकल्पित लक्ष्यों को प्राप्त करें और समुदाय की सेवा करें। सीबीआई को किसी और के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं करना पड़ा तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की तुलना में बिगड़ रहा है. एमसीआई, एआईसीटीई, यूजीसी जैसी कई

नियामक संस्थाएं आदि भी हाल के वर्षों में गंभीर प्रभाव में थे। सी.बी.आई., में वर्ष 2010 में एमसीआई के अध्यक्ष को गिरफ्तार करना पड़ा में एक मेडिकल कॉलेज को मान्यता देने के लिए रिश्वत लेना पंजाब. बाद में, यह बताया गया कि सीबीआई ने पाया कि राष्ट्रपति एमसीआई और उसके परिवार के सदस्यों के पास आय से अधिक संपत्ति थी 24 करोड़ की संपत्ति. हमने इन उदाहरणों का उल्लेख किया है केवल हमारी शिक्षा प्रणाली के गिरते स्तर को इंगित करने के लिए उच्चतम स्तर पर, कभी-कभी केन्द्रीय स्तर पर भी सरकार जीवन के अधिकार पर गंभीरता से काम कर रही है के अनुच्छेद 21 के तहत देश के नागरिकों को गारंटी दी गई है

भारत का संविधान.

40. बड़ी संख्या में मेडिकल, इंजीनियरिंग, की मशरूमिंग नर्सिंग और फार्मास्युटिकल कॉलेज, जो निश्चित रूप से है इस देश में, विशेषकर में, शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हुई चिकित्सा क्षेत्र जो गंभीर आत्मनिरीक्षण की मांग करता है। निजी चिकित्सा शिक्षण संस्थान हमेशा अधिक की मांग कर रहे हैं उनके कॉलेजों में सीटों की संख्या भले ही उनमें से कई के पास है पर्याप्त ढांचागत सुविधाएं, नैदानिक सामग्री, संकाय नहीं सदस्य, आदि। रिपोर्टें समय-समय पर सामने आती रहती हैं जो निजी संस्थाएं मेडिकल कॉलेज संचालित कर रही हैं कभी लकली तो कभी करोड़ों रुपए की मांग कर रहे हैं एमबीबीएस और उनके संबंधित स्नातकोत्तर प्रवेश के लिए

कॉलेज. हाल ही में खबर आई है कि एमबीबीएस की कुछ सीटें बिक गईं चेन्नई के निजी कॉलेजों में. हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि हमारे देश में ये सब हो रहा है टीएमए पाई में इस न्यायालय द्वारा संवैधानिक घोषणाएँ फाउंडेशन कि कोई मुनाफाखोरी नहीं होगी या कैपिटेशन शुल्क आदि की स्वीकृति। केंद्र सरकार, मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, केंद्रीय जांच ब्यूरो या इंटेलिजेंस विंग को पूर्ववत करने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे ऐसी अनैतिक प्रथाएँ अन्यथा स्व-वित्तपोषित संस्थाएँ करेंगी छात्र वित्तपोषण संस्थान बनें।

41. हम देखते हैं कि केंद्र की वर्तमान नीति उच्च शिक्षा में सरकार को स्वायत्तता प्रदान करनी है संस्थाएँ, लेकिन अनुचित प्रथाओं को अपनाना एक गंभीर उल्लंघन है कानून का. कुछ राज्य, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली आदि कुछ आगे निकल चुके हैं कैपिटेशन शुल्क की मांग/संग्रह पर रोक लगाने के लिए कानून उनके पास कोई दांत नहीं है, जो संस्थाएं ऐसी प्रथाओं में लिप्त हैं कुछ जुर्माना देकर बच सकते हैं, जो बहुत कम है।

42. इसलिए, हम एक की अत्यधिक आवश्यकता पर जोर देते हैं इन अनुचित प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए संसदीय विधान, जो हमारे समाज की मांग है. 'अनुचित का निषेध तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सा में अभ्यास शैक्षणिक संस्थान और विश्वविद्यालय विधेयक,

2010" पहले ही आ चुका है संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया गया। यह सूचित किया है राज्यों ने इस तरह के कानून का स्वागत किया है, लेकिन इससे आगे नहीं अनुवर्ती कार्रवाई की गई है. हम आश्वस्त हैं, ईमानदार हैं उचित कानून लाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि उच्च तकनीकी और में प्रचलित अनैतिक और अनुचित प्रथाएँ व्यापक जनता में चिकित्सा संस्थानों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाया जा सकता है दिलचस्पी।

43. इसलिए, हमें अनुच्छेद को लागू करने का कोई अच्छा कारण नहीं मिलता है भारत के संविधान के 32 और मौलिक में से कोई नहीं याचिकाकर्ताओं को दिए गए अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। याचिका, इसलिए, इसमें योग्यता का अभाव है और इसे खारिज कर दिया गया है..

रिट याचिका खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशीयल इंटलीजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रवीण चैहान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आबूपर्वत, जिला सिरोही(आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंगंे्रजी संस्करण ही मान्य होगा।